अनुदान संख्या 6 – उर्वरक विभाग
GRANT No. 6 - DEPARTMENT OF FERTILISERS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	73974,95,00			
			138573,25,00	131271,10,36	-7302,14,64
पूरक	Supplementary	64598,30,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7302,14,56
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5,00			
			813,28,00	813,24,00	-4,00
पूरक	Supplementary	813,23,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹730214.64 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹6459830.00 लाख के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹730214.64 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of ₹6459830.00 lakhs obtained in February, 2021 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"				
फसल कृषिकर्म	Crop Husbandry				
मू.	O.	2350400.00			
पू.	S.	1548588.00			
पु.	R.	-161740.60	3737247.40	3737247.39	-0.01
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	5043500.00			
पू.	S.	4911242.00			
पु.	R.	-568043.14	9386698.86	9386698.86	..

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2401" – "खाद तथा उर्वरक – पोषक आधारित सहायिकी नीति" – ₹2350400.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1548588.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3898988.00 लाख किया गया जो, तथापि, मैसर्स इफको से दावों की मंजूरी न मिलने, पी एंड के फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत कम बिक्री तथा राज्य सरकार से गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण सिटी कम्पोस्ट दावों का निपटान न होने की वजह से ₹161740.61 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2401" - "Manures and Fertilizers - Nutrient Based Subsidy Policy" - the original provision of ₹2350400.00 lakhs was augmented to ₹3898988.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1548588.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹161740.61 lakhs - due to non-approval of claims from M/s IFFCO, less sale under P & K Fertilizers and non-settlement of City Compost claims due to non-receipt of quality certification from State Government.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उर्वरक उद्योग – उर्वरक सहायिकी – यूरिया सहायिकी" – ₹5043500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4911242.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9954742.00 लाख किया गया जो, तथापि, यूरिया की कम बिक्री होने, एफसीआई – रामागुंदम और मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स लि. में यूरिया का उत्पादन न होने तथा मुकदमों का निपटान न होने के कारण ₹568043.14 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2852" - "Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy - Urea Subsidy" - the original provision of ₹5043500.00 lakhs was augmented to ₹9954742.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4911242.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹568043.14 lakhs - due to less sale of urea, non-production of Urea at FCI-Ramagundam and Matrix Fertilizers Limited and non-settlement of court cases.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹429.89 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹429.89 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹4.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः उसे अभ्यर्पित किया गया।

2. In the capital section of the grant, provision of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads and was eventually surrendered.